1	2
महाराष्ट्र	10611.86
मणिपुर	274.29
मेघालय	668.43
मिजोरम	136.49
नागालैंड	107.00
उड़ीसा	9053.72
पंजाब	1595.01
राजस्थान	11602.77
सिक्किम	75.56
तमिलनाडु	3744.64
त्रिपुरा	224.18
उत्तर प्रदेश	9165.57
पश्चिम बंगाल	4115.12
अं० तथा निकोबार द्वीप समूह	12.09
चंडीगढ़	1.17
दादर और नगर हवली	17.96
दमन और दीव	1.19
दिल्ली	118.37
लक्षद्वीप	0.48
पांडिचेरी	62.14

Demands of Minority Bodies

*466. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Hindustan Times of 13th February 1994 captioned "Demand of minority bodies" regarding demands raised at the conference of State Minorities' Commissions and Boards held recently;

(b) if so, the action taken by Government so far in this regard; and

(c) how much time is likely to be taken by Government to fulfil their demands ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) Yes, Sir. The news refers to a conference of State Minorities Commission/Boards and State Minorities Finance Development Corporations held on 7th February, 1994 at New Delhi under the aegis of the National Commission for Minorities.

(b) and (c) The Commission has not formally conveyed the decisions and recommendations of the Conference to the Government so far.

However in regard to the matters referred to in the news item, a statement is laid on the Table of the House.

Statement

(i) Statutory status for State Minorities Commissions/Boards; and

(ii) Provision of adequate funds for schemes launched by State Minorities Commissions and Boards.

These are matters within the purview of the State Governments.

(iii) Inclusions of representatives of the minority communities on the Public Service Commissions and other recruiting agencies.

The Central Government has already issued instructions to all recruiting agencies of the Central Government and its Public Undertakings to include representatives of the minorities in all selections where the number of posts to be filled up is ten or more.

As regards recruitment at the State level, the matter is within the purview of the State Governments.

(iv) Setting up of Special Courts.

As per informaiton furnished by State Governments/Government of Delhi, the number of Special Courts set up for trial of cases relating to communal crimes is indicated below :

Name of State/UT	No. of Special Courts
Andhra Pradesh	3
Bihar	13
Gujarat	5
Karnataka	6
Rajasthan	17
Delhi	3
TOTAL :	47

(v) Autonomy or minority educational institutions.

In pursuance of the Constitutional safeguards enshrined in Articles 29 and 30 of the Constitution, Government have issued policy norms and principles for recognition of minority educational institutions which prohibit laying down such conditions as would render the constitutional rights of the minorities nugatory.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शैक्षिक विकास हेतु योजना

*468. **श्रीमती चान्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के शैक्षिक विकास हेतु योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए ऐसा कोई शैक्षिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार तथा जिले-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कबालू) : (क) बहुत कम साक्षर स्तर से संबंधित अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना जिसमें आवासीय स्कूल परिसरों की स्थापना करने की व्यवस्था है, को अभी आरंभ किया जाना है चूंकि इसकी रूपरेखा को योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, लड़कियों सहित अनुसूचित जाति छात्रों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्तियां, पाठ्य पुस्तकें तथा होस्टल सुविधाएं देने हेतु सरकार की अन्य योजनाएं हैं जैसा कि संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। **(नीचे देखिए)** राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों का कम साक्षर क्षेत्रों में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करने हेतु विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने की अनुमति भी दी जाती है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी क्षेत्रों सहित आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षर पाकेटों में, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए 1993-94 में एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरम्भ की गई है।